भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1029
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सतत विमानन पद्धतियों को बढ़ावा

1029. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सतत विमानन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र से विशेष रूप से विमान प्रौद्योगिकी, प्रचालनात्मक दक्षता और वैकल्पिक ईंधनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई पहल कार्यान्वित की है अथवा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुसार डीजीसीए द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित परिचालनों के कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी की जाती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाईअड्डों के कार्बन लेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकृत करके देश में हवाईअड्डों पर कार्बन न्यूट्रैलिटी की दिशा में काम करने और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पहल की है। इस प्रयोजन के लिए, निर्धारित परिचालन वाले हवाईअड्डा ऑपरेटरों को अपने संबंधित हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का मानचित्रण करने और चरणबद्ध तरीके से कार्बन तटस्थता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में काम करने की सलाह दी गई है।

नागर विमानन मंत्रालय ने आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों और संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपर्स को कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट ज़ीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है। भारत सरकार के उपरोक्त प्रयासों से, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाईअड्डों ने लेवल 4+ और उच्चतर हवाईअड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (एसीआई) मान्यता प्राप्त कर ली है और वे कार्बन न्यूट्रल हो गए हैं। 70 भारतीय हवाईअड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं।

विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में बायो-एटीएफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बायो-एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) कार्यक्रम समिति का गठन किया था। समिति की संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे माल का उत्पादन/मांग, प्रौद्योगिकी, बीआईएस मानक, इंजन निष्पादन पर प्रभाव आदि शामिल थे। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, देश में आने वाले सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) संयंत्रों की क्षमताओं और अनुमानित एटीएफ बिक्री के लिए, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा शुरू में एटीएफ में एसएएफ के निम्नलिखित प्रारंभिक सांकेतिक मिश्रण प्रतिशत को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमोदित किया गया है: वर्ष 2027 तक 1% एसएएफ सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य, वर्ष 2028 तक 2% एसएएफ मिश्रण लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 5% एसएएफ सम्मिश्रण लक्ष्य।

******